



जल है तो कल है

**प्रेरणा**  
सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है।

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-5 • 01 MARCH TO 07 MARCH 2024 • VOLUME 32 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

**INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE**

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

✓ STUDY ✓ WORK ✓ SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges & \*Pay Money after the Visa

**IELTS • STUDY ABROAD**

CANADA AUSTRALIA USA

U.K SINGAPORE EUROPE

## बादल परिवार ने निजी लाभों के लिए पंजाब के लोगों के करोड़ों लूटे : सीएम

निजी कारोबार को लाभ पहुंचाने के लिए हर नियम व नीति की धजियाँ उड़ाने के लिए दोष

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

अपने निजी लाभों के लिए राज्य के करोड़ों रुपए लूटने वाले बादल परिवार की आलोचना करते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली-भाजपा गठजोड़ सरकार ने सुख विलास होटल के निर्माण के लिए अकाली नेता सुखवीर सिंह बादल के पक्ष में नियमों को तोड़ा-मरोड़ा। यहाँ पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार 2009 में इको-टूरिज्म नीति लेकर लाई, जिसका एकमात्र उद्देश्य इस रिजोर्ट के निर्माण में मदद करना था। उन्होंने कहा कि यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि एक पोल्ट्री फार्म को एक रिजोर्ट में तबदील कर दिया गया और टैक्सों के रूप में इस रिजोर्ट के 108 करोड़ रुपए माफ करके राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि गाँव पल्लनपुर में बने इस रिजोर्ट का असली नाम मेट्रो इको ग्रीन रिजोर्ट है, जिसको बाद में सुख विलास का नाम दिया गया। पंजाबियों के खून से बना यह सुख विलास वास्तव में पंजाब के लिए दुख विलास है।



मुख्यमंत्री ने अफ़सोस ज़ाहिर किया कि उस समय के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस रिजोर्ट का 10 सालों के लिए एस. जी. एस. टी. और वेट का 75-75 प्रतिशत हिस्सा माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत एस. जी. एस. टी. और वेट के कुल 85 करोड़ रुपए माफ किये गए। इसके इलावा 10 सालों के लिए 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी माफ की गई, जो 11.44 करोड़ रुपए बनती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यही नहीं इस रिजोर्ट का 11 करोड़ रुपए का लगररी टैक्स और लायसेंस फीस भी माफ की गयी, जिससे राज्य के खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रिजोर्ट के लिए टैक्सों के रूप में 108.73 करोड़ रुपए माफ किये गए और यह सारा पैसा बादलों

के निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि इस पैसे का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2009 में लाई इस नीति का लाभ किसी कंपनी को नहीं दिया गया, बल्कि इसका प्रयोग बादलों ने सिर्फ अपनी निजी लाभ के लिए किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुख विलास को जाती सड़क का निर्माण भी गमाड़ा द्वारा करदाताओं के पैसे के साथ किया गया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस रिजोर्ट के लिए वन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया, जबकि यह रिजोर्ट अपने एक कमरे का चार से पाँच लाख रुपये किराया वसूलता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रिजोर्ट का 11 मई, 2015 से 10 मई, 2025 तक के समय का टैक्स माफ किया गया। उन्होंने आगे बताया कि इस रिजोर्ट की मालिक कंपनी में हरसिमरत कौर बादल के नाम पर 81, 500 शेयर और बादलों की ही मालिकी वाली डबबवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पर 5350 शेयर हैं। भगवंत सिंह मान ने एलान किया कि राज्य के खजाने के एक-एक पैसे की वसूली की जायेगी और इस सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी विस्तृत जांच चल रही है कि इस रिजोर्ट के निर्माण के लिए कौन से कानूनों का प्रयोग या कौन से कानूनों को तोड़ा-मरोड़ा गया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि करदाताओं के एक-एक पैसे की रिकवरी की जायेगी।

## 8.4 प्रतिशत की दर से ग्रोथ पर देश की जीडीपी, पीएम ने दी बधाई

नई दिल्ली. देश की जीडीपी की दिसंबर तिमाही के आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं। तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी तेजी आई है। सरकार ने आंकड़े जारी कर बताया कि तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4 प्रतिशत की दर से हुई है। सरकार का यह आंकड़ा पूर्वानुमान से अधिक है। देश में निर्माण कार्य में तेजी व सरकारी खर्च में तेजी के चलते जीडीपी की ग्रोथ तेज हुई है। पिछले तिमाही की जीडीपी 7.6 प्रतिशत रही। पीएम मोदी ने ट्वीट कर भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के आंकड़े शेर कर बधाई दी है। धानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अर्थव्यवस्था का तेज



गति से विकास करें जिससे देश के 140 करोड़ नागरिक बेहतर जीवन को जी सके और विकसित भारत को साकार कर सकें। भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 29 फरवरी को जीडीपी ग्रोथ संबंधी आंकड़े जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी दिसंबर तिमाही में तेजी से आगे बढ़ी है। जीडीपी ग्रोथ इस तिमाही 8.4 प्रतिशत की दर से दर्ज की गई है जोकि पूर्वानुमानित दर 6.6 फीसदी की दर से कहीं ज्यादा है।

## गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, वीजा व पासपोर्ट हो सकता है रद्द

हरियाणा. किसानों और पुलिस फोर्स के बीच पिछले कई दिनों से जमकर संघर्ष देखने को मिल रहा है। किसानों और हरियाणा पुलिस फोर्स के बीच ये संघर्ष शंभू बाँडर पर देखने को मिला। डीएसपी अंबाला जोगिंदर शर्मा ने कहा है कि आंदोलन की आड़ में कई लोगों की ओर से पत्थरबाजी की गई। हिंसा में शामिल कथित किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने किसानों के विरोध के नाम पर पंजाब से हरियाणा आने वाली हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की है। इसके अलावा हमने सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से उनकी पहचान की है। हम मंत्रालय और दूतावास से उनके वीजा और पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध कर रहे हैं। उनका तस्वीरें, नाम और पता पासपोर्ट कार्यालय को दिया जाएगा। हम उनके पासपोर्ट रद्द करने पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें हमने ऐसी ली हैं, जिसमें कई लोग अलग-अलग तरह से उपद्रव मचा रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली चलो मार्च शुरू होने पर किसानों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई। पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया ताकि लोग बैरिकेडिंग न तोड़ सकें।

## फर्जी विजीलेंस अधिकारी बन की धोखाधड़ी, गिरफ्तार

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने पिन्डर सोढी निवासी कब्जा चम्बवाल, जिला होशियारपुर को गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने और उसके साथियों ने अपने आप को विजीलेंस मुलाज़िम बता कर एक किसान से 25 लाख रुपए के दो चैक लिए थे जिस कारण उनको अदालत द्वारा भगोड़ा करार दे दिया गया था।



शहर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है परन्तु मुख्य मुलाज़िम पिन्डर सोढी और हरदीप सिंह निवासी खमाणों कब्जा फ़रार

थे और उनको इस साल जनवरी में अदालत द्वारा पी. ओ. एलान कर दिया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य दोषी पिन्डर सोढी को ब्यूरो के मुलाज़िमों ने बहुत मुश्किली के साथ सैक्टर 32, बी. सी. एम. स्कूल के नजदीक, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना के एक पार्क के नजदीक उस समय गिरफ्तार किया जब वह अपनी मारुति सविफ्ट कार पी. बी. - 07 सी. डी. - 2603 में भागने की कोशिश कर रहा था। मुलाज़िम की उन्नत कार की तलाशी के दौरान मानवाधिकार आयोग के कई लोगों, तीन मोबाइल फ़ोन, यू. ए. ई. देश का ड्राइविंग लायसेंस, भारतीय करेंसी नोट समेत 305 दिरहाम के करेंसी नोट बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि दोषी पिन्डर सोढी को कल अदालत के समक्ष पेश किया जायेगा और इस मामले को आगे जांच जारी है।

## हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर कार्रवाई के डर से जीरो एफआईआर हुई : बाजवा

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़



• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शूभकरण सिंह की हत्या के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ जीरो एफआईआर तभी दर्ज की जब उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, 'पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई के डर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाटारों थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 114 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। अन्यथा, वह पिछले सात दिनों से क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि प्राथमिकी में उल्लेख है कि अगर शूभकरण की हत्या इस पुलिस थाने (पाटारों) की सीमा के बाहर हुई है तो इसे हरियाणा के जौद जिले के गढ़ी पुलिस थाने में रेफर किया जा सकता है। यह स्थापित किया गया कि आप सरकार ने यह प्राथमिकी गलत इरादे से दर्ज की थी। यह एफआईआर और कुछ नहीं बल्कि दिखावा है। बाजवा

ने कहा कि प्राथमिकी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ सीधे प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की जा सकती है, जबकि उन्होंने ही पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ क्रूर बल प्रयोग करने का निर्देश दिया था? यह एक बहुत ही कमजोर एफआईआर है और अदालत को जटिल कार्यवाही के दौरान टिक नहीं पाएगी। आप सरकार ने शूभकरण सिंह के परिवार को धोखा दिया है।

याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था। तभी मान सरकार गहरी नींद से जागी और जीरो एफआईआर दर्ज कराई। इस बीच, भगवंत मान को पंजाब के लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्हें पहले कानूनी कार्रवाई करने से किसने रोका था।

विपक्षी नेता ने कहा कि शूभकरण सिंह की मौत पर कार्रवाई के विवरण के बारे में बार-बार पूछताछ करने के प्रयासों के बावजूद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कोई भी विवरण देने से इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारी यह भी बताते हैं कि वे इस मुद्दे पर अब तक चुप क्यों रहे और मूकदर्शनक बने रहे। कुछ खबरों का हवाला देते हुए बाजवा ने उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह बात भी लाई कि कुछ प्रदर्शनकारियों के चेहरे, माथे पर प्लैटर गन के निशान भी लगे हैं।

## अंतरराष्ट्रीय नाकों स्मगलिंग और अंतर-राज्यीय हथियारों की तस्करी के कार्टेल का पर्दाफाश; 5 किलो हेरोइन, 4 हथियारों सहित तीन काबू

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़/अमृतसर

कमिशनर अमृतसर पुलिस ने 5 किलो हेरोइन समेत नशा तस्करी को काबू करके अमरीका स्थित जसमीत उर्फ लक्की की हिमायत वाले अंतरराष्ट्रीय नाकों समगलिंग कार्टेल का पर्दाफाश किया है। पंजाब के डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि पकड़े गए नशा तस्करी की पहचान गुरप्रीत कुमार उर्फ दीप (27) निवासी न्यू शांति नगर भजवाड़ा



होशियारपुर के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने हेरोइन की सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जा रही टाटा ए. सी. ई. न्यू शांति नगर भजवाड़ा 07- ए. एल. - 9743) को भी ज़ब्त किया है। डीजीपी ने बताया कि एक अन्य मामले में कमिशनर अमृतसर पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को

गिरफ्तार करके उनके कब्जे में से चार देसी पिस्तौलों सहित चार मैगजीनों और 16 जिंदा कारतूस बरामद करके एम. पी. आधारित हथियार सप्लाई करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान हरमिन्दरपाल सिंह (23) और जतिन्दरपाल सिंह (23) बाबा (20) दोनों निवासी गुरू नानक कालोनी अमृतसर के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने उनका एकटवा स्कुटर ( पी. बी. 02- ई. एस.-0344) भी कब्जे में लिया है, जिस पर वह

हथियारों की खेप पहुँचाने जा रहे थे। पुलिस कमिश्नर (सी. पी.) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि भरोसेयोग्य सूचना पर कार्यवाही करते हुये पुलिस टीमों ने गाँव कार्जाकोट से चम्बवाल रोड की तरफ जाकर मुलाज़िम गुरप्रीत कुमार उर्फ दीप को काबू किया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान काबू किये कथित दोषी गुरप्रीत कुमार ने खुलासा किया कि वह अमरीका आधारित जसमीत उर्फ लक्की के इशारे पर सरहद पार से हेरोइन की खेप ला रहे थे।

## पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसज़ लोगों को समर्पित

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा- लोगों को विश्व स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं हासिल होंगी

• जालंधर ब्रीज. एसएस नगर

राज्य की सरकारी संस्थाओं की बदहाली के लिए अकाली और कांग्रेसी सरकारों को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराते हुये मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार अब सरकारी संस्थाओं में अब्बल दर्जे की सहूलतें प्रदान कर रही है जिससे पंजाब का कोई भी व्यक्ति सरकारी सहूलतों का लाभ लेने से वंचित न रहे। इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डाक्टर बलबीर सिंह और सांस्कृतिक मामलों और पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान भी उपस्थित थे। गुरुवार को यहां 'पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसज़' लोगों को समर्पित करने के बाद इन्स्ट्रुट को संबोधन करते हुये कहा कि पिछली सरकारों के मौके

पर राजनीतिज्ञ प्राइवेट संस्थाओं के कारोबार में से हिस्सेदारी लेते थे और इसके एवज़ में सरकारी संस्थाओं को बिल्कुल ही अनदेखा कर देते थे। राज्य में अब सरकारी संस्थाओं की बेहतरी के लिए उठाये जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने मिसाल

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में 45 जच्चा- बच्चा देखभाल केंद्र स्थापित कर रही है जिनमें से 37 लोगों को समर्पित किये जा चुके हैं। पिछली सरकारों के हितोत्साहित करने वाले सिस्टम से नाराज़ हो चुके विदेश जाने वाले नौजवानों की 'वतन वापसी' (रिवर्स माईग्रेशन) की मिसाल देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि दो सालों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है जिससे तीन लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा।



नेताओं को दी पंजाबी की परीक्षा पास करने की चुनौती : मुख्यमंत्री ने अकाली नेता हरसिमरत बादल, बिक्रम सिंह साईंसज़ देश की दूसरी और पंजाब की पहली प्रतिष्ठित संस्था है जिसके पास इतनी आधुनिक मशीनें हैं कि किसी प्राइवेट अस्पताल के पास भी नहीं हैं।

पंजाबी भाषा की लिखित परीक्षा पास करने की चुनौती दी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह नेता कान्वेंट स्कूलों से पूरे हुये हैं जिस कारण यह पंजाबी भाषा की परीक्षा पास ही नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वह इन नेताओं को सवालों के जवाब भी बता दें तो भी वह उत्तर सही नहीं लिख सकते।

फंड रोकने पर केंद्र की आलोचना : केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के फंड रोकने की सख्त आलोचना करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गैर-भाजपा राज्य सरकारों के साथ नफ़रत और भेदभाव करती है जिस कारण पंजाब की तरह दिल्ली, केरला, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्य अपने फंड लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए मजबूर हैं।



## अनुराग सिंह ठाकुर ने की चंडीगढ़ में 'फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय' खोलने की घोषणा

सीबीएफसी का सुविधा कार्यालय खुलने से क्षेत्रीय फिल्मों के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी, पंजाबी फिल्म उद्योग लाभान्वित होगा

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का एक क्षेत्रीय सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के फिल्म निर्माताओं के लिए व्यवसाय करने को और भी अधिक आसान बनाना है। आज चंडीगढ़ में 'चित्र भारती फिल्म महोत्सव' के समापन समारोह में इस आशय की घोषणा करते हुए ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र के फिल्म निर्माता अपनी-अपनी फिल्मों के लिए सीबीएफसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दिल्ली या मुंबई जाए बिना ही अपनी-अपनी फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ उनमें विभिन्न कट्स/संशोधनों को प्रस्तुत करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से पंजाबी फिल्म उद्योग को और भी अधिक मजबूती मिलेगी। मंत्री महोदय ने यह भी कहा, "आज भारत को एक कंटेंट हब के रूप में देखा जा रहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग व फिल्म निर्माण के बाद की प्रक्रिया दोनों ही के लिए पसंदीदा देश बनता जा रहा है।

समानांतर रूप से हमारे अपने कंटेंट को दुनिया भर में काफी सराहा जा रहा है।" यह बताते हुए कि हर साल दुनिया में बनने वाली 2500 फिल्मों में से आधे से अधिक भारत में बनती हैं, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "फोन फिल्मों से लेकर वृत्तचित्र



और लघु फिल्मों से लेकर धारावाहिकों तक, भारतीय सिनेमा आज जीवन के हर रंग को अपने कैनवास पर चित्रित कर रहा है और स्थानीय कहानियों को वैश्विक स्तर पर पहुंचा रहा है।" इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म किस भाषा में बनाई जा रही है। जब तक कंटेंट दिलचस्प रहेगा, तब तक उसके प्रशंसक हमेशा बने रहेंगे।" ठाकुर ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब में बनने वाली फिल्मों में भी अपार संभावनाएं हैं। इसलिए, सरकार ने चंडीगढ़ में एक सीबीएफसी का सुविधा कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि प्रमाणन हासिल करने की प्रक्रिया आसान हो और फिल्म को पूरा करने की प्रक्रिया तेज हो।" केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से दिव्यांग फिल्म प्रशंसकों के लिए सिनेमाघरों की और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न पहल के बारे में भी बात की।

सरकार ने इस संबंध में एक नया

दिशानिर्देश तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों से पहले ही टिप्पणियां आमंत्रित की हैं ताकि श्रवण एवं दृष्टिबाधित लोगों को अन्य लोगों की तरह ही फिल्म का आनंद लेने का अवसर मिल सके। "इस देश के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण रहा है।

विकलांग के बजाय दिव्यांग कहने वाले वह पहले व्यक्ति हैं। उनके द्वारा आभिव्यक्त की गई रुचि के कारण ही सरकार ने प्रत्येक फिल्म के दिव्यांगों के लिए उपयुक्त संस्करण को जारी करने का दायित्व अपने ऊपर लिया है।" "पायरेसी के खतरे पर बोलते हुए, ठाकुर ने कहा, "हमने हाल ही में फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में बहुत सार्थक बदलाव किए हैं। आज, पायरेसी को रोकने के लिए हमारे सभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) केंद्रों पर विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। देश

भर में 12 नोडल अधिकारी पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड कंटेंट को हटाने के निर्देश देंगे। शिकायत मिलने के 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

पायरेसी न केवल फिल्म उद्योग के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है।" रिपोर्ट्स के मुताबिक, पायरेसी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को हर साल 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। ठाकुर ने चित्र भारती फिल्म महोत्सव के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा, "युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और उन्हें हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रतिबिंबित करने वाली सार्थक फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए किए जा रहे प्रयास वास्तव में सराहनीय हैं। मैं इसे देखने के लिए उत्सुक हूँ। इनमें से कई फिल्में निकट भविष्य में दुनिया भर के प्रमुख फिल्म महोत्सवों में प्रदर्शित होंगी।"

## मोदी सरकार का तोहफ़ा, हिमाचल से हरिद्वार के लिए अब सीधी ट्रेन सुविधा: अनुराग ठाकुर

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली/ हि.प्र.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जानकारी देते हुए बताया की ऊना हिमाचल से चल कर सहारनपुर जाने वाली ट्रेन अब हरिद्वार तक चलाई जाएगी।

अनुराग ठाकुर ने उपरोक्त निर्णय हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री



अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि इससे क्षेत्रवासियों को काफी लाभ मिलेगा और तीर्थयात्रा में बढ़ोतरी होगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा "केंद्र में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल का प्रतिनिधि होने के नाते मैं सदैव यहां के विकास हेतु कार्यरत हूँ व हिमाचल प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता में है। हरिद्वार एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और हिमाचल से बड़ी संख्या में लोग तीर्थयात्रा करने हरिद्वार जाते हैं। हिमाचल के यात्रीगण ट्रेन से सीधा ही हरिद्वार तक जा सकें ऐसी सुविधा के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अनुरोध किया था। मुझे यह बताते हुए

हर्ष हो रहा है कि ऊना हिमाचल- सहारनपुर MEMU जो ऊना से चल कर सहारनपुर तक जाती थी उसके एक्सटेंशन की मंजूरी रेलमंत्री जी ने दे दी है। यह ट्रेन अब ऊना से हरिद्वार तक चलाई जाएगी जिससे यात्रियों को आवागमन की बड़ी सुविधा मिलेगी। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करता हूँ।

अनुराग ठाकुर ने कहा "विकास ही हमारी प्राथमिकता है और मोदी सरकार ने ऊना को सीगातः देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की चौथी वन्दे भारत ट्रेन की सीगातः हिमाचल को दी जिसके शुभारंभ के लिए खुद मोदी जी ऊना आये थे। हिमाचल में अब हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन भाजपा के कारण ही चल पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में रेलसेवाओं का विस्तार हो, हिमाचल को कनेक्टिविटी से जुड़ी कोई समस्या ना हो इसके लिए मोदी सरकार नई ट्रेनें चलाने से लेकर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इत्यादि पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। वित्तवर्ष 2023 - 24 के लिए हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सामरिक महत्व की भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन के लिए 1000 करोड़, चंडीगढ़-बदली रेललाइन को 450 करोड़ रुपये, गंगल- तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ रुपए वर्ष 2023-24 के बजट में मंजूर किए गए हैं। रेल विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपए की यह मंजूरी यूपीए शासन काल के वर्ष 2009 - 2014 से 17 गुना ज़्यादा है। वर्तमान में प्रदेश में रुपए 19556 करोड़ से 258 किलोमीटर की 4 परियोजनाओं पर काम जारी है।"

## पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में मंत्री सोम प्रकाश ने प्रशासनिक भवन एवं केंद्रीय पुस्तकालय की रखी आधारशिला

• न्यूज़ हंट. बटिडा

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश ने प्रशासनिक भवन एवं केंद्रीय पुस्तकालय की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी व उनके कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार ए प्रेड प्राप्त करने और भारत के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान हासिल करने की विश्वविद्यालय की उल्लेखनीय उपलब्धि प्रोफेसर (डॉ.) राघवेंद्र प्रसाद तिवारी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतिफल है। माननीय मंत्री सोम प्रकाश ने भारत के प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के कार्यों को स्मरण करते हुए कहा कि दो सौ साल तक हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया उस समय हमारी आर्थिक स्थिति निम्नतम स्थान पर थी अब हम विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और 2047 तक हम विश्व के देशों में प्रथम स्थान पर होंगे। अपने मुख्य संबोधन में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने युवा पीढ़ी की क्षमताओं पर आशा व्यक्त करते हुए माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने व भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि और व्यापार करने व देश की उच्च रैंकिंग से वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व



और प्रतिबद्धता को दिया। कार्यक्रम में कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी द्वारा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश को शाल एवं विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने अपने स्वागत भाषण पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण भारत की सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रतिनिधित्व को रखांकित किया।

उन्होंने कहा लगभग 36 करोड़ रुपये से निर्माणाधीन प्रशासनिक एवं पुस्तकालय भवन के निर्माण से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु अधिक सुविधाएं मिलेंगी। कुलपति ने शिक्षा मंत्री माननीय धनंजय प्रधान का भवनों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।

कुलपति ने कहा कि देश के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश ने बहुत ही कम समय में अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में

से समय निकलकर हमें यह अवसर दिया।

प्रो. तिवारी ने माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश की सरलता एवं सहजता का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि हमें इस सहजताबोध से सीखने की आवश्यकता है। कुलपति प्रो. तिवारी ने विश्वविद्यालय परिसर में पुस्तकालय एवं प्रशासनिक भवन के शिलान्यास होने पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा इसको और गतिशील बनाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता दुहराया। विश्वविद्यालय के कुलसचिव विजय कुमार शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का सञ्चालन प्रो. संजीव ठाकुर ने किया। इस अवसर पर प्रभारी अधिष्ठाता अकादमिक प्रोफेसर रामकृष्ण वसुदेवक, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बी.पी. गर्ग, निदेशक आईक्यूएसी मोनिशा धीमान, सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, विद्यार्थी व शोधार्थी, अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

## खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण- मोदी की गारंटी

ऐसे समय में जब युद्ध, मौसम और अस्थिरता के चलते पैदा हुई बाजार की नाजुक स्थिति की वजह से वैश्विक खाद्य आपूर्ति दबाव में है, उपभोक्ताओं और किसानों के हितों की दृष्टि से भारत में स्थितियां अंधाधुंध बेहतर हैं। गुरुवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 8 प्रतिशत बढ़ा दिया है। गन्ना किसानों को पहले से ही विश्व में गन्ने का सबसे अधिक मूल्य मिल रहा है, जबकि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भारतीय उपभोक्ताओं को विश्व में सबसे सस्ती चीनी उपलब्ध हो। इस प्रकार की पहलों की एक श्रृंखला है, जो किसान कल्याण को उपभोक्ता हितों के साथ जोड़ती है।

इस महीने की शुरुआत में, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक नागरिक को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए, 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर "भारत राइस" का शुभारंभ करके एक बार फिर देश के नागरिकों को किफायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित की है। इसके लिए हम कड़ी मेहनत करने वाले हमारे किसानों को धन्यवाद देते हैं, जो अधिकांश कृषि वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन करके देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80

करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा बाकी आबादी के लिए भी खाद्य उत्पादों की बहुत ही उचित कीमत तय की गई है। भारत राइस, आटा, दाल- मोदी सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि से निपटने के लिए हमेशा



जालंधर ब्रीज

पीयूष गोयल

(केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक विद्युत और वस्त्र मंत्री, भारत सरकार)

तेजी से काम किया है। पिछले वर्ष, सरकार ने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक सब्सिडी दर पर "भारत दाल" और 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की कम कीमत पर "भारत आटा" लॉन्च किया था। इसी प्रकार केंद्रीय एजेंसियां सस्ता प्याज बेचती हैं। इन्होंने उस समय भी टमाटर की आपूर्ति की, जब इसकी कीमतें आसमान छू रही थी, केंद्र सरकार ने कीमतों में इस अंतर का भारी बोझ उठाया। "भारत" खाद्य पदार्थों की बिक्री तेजी से बढ़ी है और ये पदार्थ 18,000 से अधिक दुकानों पर उपलब्ध हैं। अभूतपूर्व, तेजी- इससे पहले कभी भी केंद्र सरकार ने खुदरा बाजार में खाद्यान्न

या दालें नहीं बेचीं। इनके मूल्यों पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री मोदी हमेशा निर्णायक कदम उठाते रहे हैं। पिछले वर्ष, जैसे ही बेमौसम की बारिश ने टमाटरों की आपूर्ति में बाधा डाली तो सरकार तुरंत हस्तगत में आई जिससे टमाटर की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि अच्छी गुणवत्ता वाली दाल, चावल और आटे की आपूर्ति किफायती दरों पर की जाए। ये उपाय समाज के हर वर्ग को मदद के लिए बिना किसी भेदभाव के लागू किए गए हैं। इस सरकार की एक अन्य अभूतपूर्व कार्रवाई त्वरित बाजार उपायों के लिए कृषि-बागवानी वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाने के लिए एक समर्पित मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया। सरकार ने 27,489 करोड़ रुपये की संचयी बजटीय सहायता से प्रमुख दालों और प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एी ऐतिहासिक पहल की है। सरकार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जमाखोरी या बाजार में हेराफेरी करने की कोई भी कोशिश भारी पड़ेगी। हालांकि, कुछ महीनों में ही गेहूँ की रिकॉर्ड फसल होने का अनुमान है, परंतु सरकार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। सरकार ने गेहूँ पर स्टॉक सीमा लागू कर दी है और बाजार में गेहूँ की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भी तैयार है। रोजाना 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों पर नजर रखी जा रही है।

## हिमाचल का विकास मोदी की गारंटी : अनुराग ठाकुर

• जालंधर ब्रीज . हिमाचल प्रदेश

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सोलन और बिलासपुर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर कलार बाला गांव से नौनी चौक तक मौजूदा सड़क को पेव्ड शोल्डर के साथ फोर लेन में अपग्रेड करने हेतु 1244.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार प्रकट किया है।

अनुराग ठाकुर ने हिमाचलवासियों को इस सीगातः हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी

ने हिमाचल प्रदेश को सदैव अपना दूसरा घर माना है और इसके विकास को प्राथमिकता दी है। हिमाचल प्रदेश को मोदी सरकार ने सड़क से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का तोहफ़ा दिया है। आज हिमाचल प्रदेश के सोलन और बिलासपुर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर कलार बाला गांव से नौनी चौक तक मौजूदा सड़क को पेव्ड शोल्डर के साथ फोर लेन में अपग्रेड करने हेतु 1244.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र की मोदी सरकार की ओर से मिली है। इस मंजूरी से शिमला, कांगड़ा, धर्मशाला और मंडी के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दाड़लाघाट और एम्स के लिए भी कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। मैं इस मंजूरी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार प्रकट

करता हूँ। आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा "सड़कें पहाड़ों की लाइफलाइन हैं और पहाड़ों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार सदा ही प्रतिबद्ध रही है। इसी का प्रमाण है कि अगर मैं सिर्फ़ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करूँ तो आज किरतपुर-नेरचौक फोर लेन रोड बनकर तैयार हो चुका है। मटीर-हमीरपुर-बिलासपुर शिमला फोर लेन, नेर चौक फोर लेन बनवा कर तैयार करवाया जा चुका है। एम्स 1200 करोड़ रुपये से हमीरपुर-धर्मपुर-मंडी हाईवे पर का काम जारी है। अम्ब से नादौन तक राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण व सुधार कार्य 100 करोड़ की लागत से पूरा हो चुका है। 33.10 करोड़ रुपये की धनराशि से हमीरपुर बाईपास का निर्माण पूरा हो चुका है।"

## रिजर्व बैंक आंबड्समैन चंडीगढ़ ने सरकारी अधिकारियों के बीच वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया

• जालंधर ब्रीज . चंडीगढ़

रिजर्व बैंक लोकपाल कार्यालय, चंडीगढ़ ने दिनांक 27 फरवरी 2024 को आरबीआई चंडीगढ़ में सरकारी अधिकारियों के साथ आमने-सामने बातचीत की। सरकारी अधिकारियों में दूरदर्शन, आकाशवाणी और प्रेस सूचना ब्यूरो के अधिकारी शामिल थे। आयोजन का उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच वित्तीय जागरूकता बढ़ाना और उन्हें वित्तीय क्षेत्र के बारे में शिक्षित करना था ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम को मुख्य रूप से राजीव द्विवेदी, रिजर्व बैंक लोकपाल और राम स्वरूप, उप लोकपाल ने संबोधित किया।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ग्राहकों के अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में भी बताया। प्रतिभागियों को ओटीपी, खाता/कार्ड विवरण, पिन, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड आदि साझा न करने के रूप में सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में जागरूक किया गया। वक्ताओं ने वित्तीय क्षेत्र के ग्राहकों से



आग्रह किया कि उन्हें केवल सेवा प्रदाताओं के आधिकारिक एप, वेबसाइट और कॉल सेंटर नंबर का ही उपयोग करना चाहिए। छोटे वीडियो के माध्यम से, प्रतिभागियों को वित्तीय क्षेत्र के भोले-भाले ग्राहकों को धोखा देने के लिए धोखेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले 'सामान्य तरीके' के बारे में भी अवगत कराया गया। इस संबंध में उनसे आरबीआई की वेबसाइट ( <https://www.rbi.org.in> ) पर उपलब्ध 'वी(अ)वेयर' पुस्तिका पढ़ने का भी अनुरोध किया गया। प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि मोबाइल पर केवाईसी विवरण अपडेट करने, बिजली का कनेक्शन काटने, सिम कार्ड ब्लॉक करने, क्रेडिट कार्ड में रिवाइड पॉइंट भुनाने, टेलीग्राम के माध्यम से नौकरी की पेशकश आदि जैसे किसी भी लिंक को

डाउनलोड करके या अन्यथा आने वाले संदेशों पर अत्यधिक सावधानी से बरतनी चाहिए। इसी प्रकार, विश्वी रिप्रेटदारों को निधियों के विप्रेषण के संबंध में प्राप्तकर्ताओं को दिए गए किसी भी संदेश पर उचित पुष्टि के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि बैंकों की सेवाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं में कमी के संबंध में शिकायतें रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (आरबीआईओएस-2021) के तहत जांच के लिए <https://www.cms.rbi.org.in> पर दर्ज की जा सकती है। यह मुख्य महाप्रबंधक, केंद्रीय प्राप्ति एवं प्रसंस्करण विभाग, रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17 ए, चंडीगढ़ -160017 को भेजी जा सकती है। हर्षित नारंग, भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस), उप निदेशक, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), चंडीगढ़, उमेश कश्यप, प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, कार्यक्रम प्रमुख, दूरदर्शन (प्रसार भारती) और पूनम अमृत सिंह, कार्यक्रम प्रमुख, ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी), चंडीगढ़ ने अपनी टीमों के साथ बातचीत में भाग लिया।

## 'हर काम देश के नाम'

किसी भी महत्वाकांक्षी राष्ट्र को अपना दृष्टिकोण निर्धारित करना होता है और सभी नागरिकों को वांछित दृष्टि, मिशन और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समान रूप से जिम्मेदार हितधारक और योगदानकर्ता बनना होता है। ऐसी प्रतिबद्धता को राष्ट्र के भीतर ही सभी दोष रेखाओं को दूर करना चाहिए। भारत इस तथ्य से अछूता नहीं है, इतिहास भारत की भव्यता और उसकी संपदा को लुप्तने के लिए किए गए आक्रमणों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कई लूटपाट अभियान हुए, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से भी बदतर था, जिसने भारत के ज्ञान, सामग्री, संस्थानों और आत्मसम्मान की संपदा को हानि पहुंचाई। भारत के सदियों तक गुलाम रहने का सबसे महत्वपूर्ण कारण सुरक्षा की उपेक्षा, आक्रमणकारियों और औपनिवेशिक शक्तियों के इरादों का गलत आकलन और आंतरिक सामंजस्य का कमजोर होना था।

2024 में भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उल्लिखित राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य 2047 तक 'विकसित और सुरक्षित देश' यानी एक विकसित और सुरक्षित राष्ट्र बनाना है, जो कि ब्रिटेन से स्वतंत्रता के 100 वर्षों के समकालिक है। यह यूरोपीय साम्राज्यवादी भारतीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट करने वाली शक्ति साबित हुआ।

1700 ईस्वी की शुरुआत में 27% वैश्विक जीडीपी योगदानकर्ता होने से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां खुद को स्थापित किया था, 1940 के दशक में जब शोषकों ने अंततः भारत छोड़ा, भारत मुश्किल से 3% वैश्विक जीडीपी योगदानकर्ता रह गया। औपनिवेशिक शक्ति भारत की अकांक्षा



जालंधर ब्रीज

ले जनरल वीजी खंडेर

(रिजर्व बैंक)

और भावना को नष्ट नहीं कर सकी, भारत का अस्तित्व हजारों वर्षों की विरासत और इतिहास है, जो इसे एक समृद्ध सांस्कृतिक सभ्यता के रूप में स्थापित करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ई. में हुआ था, जिसने समाज के सभी वर्गों की दिनचर्या के क्षेत्रों में बल, छल और गुलामी के माध्यम से भारत को बर्बाद करने की शुरुआत की थी। अंतिम परिणाम ब्रिटिश साम्राज्य पर हर आम आदमी और स्वदेशी संस्था की निर्भरता बनाने के लिए स्थानीय प्रणालियों और विशेषज्ञता का शोषण और हेरफेर करना था। जिससे दृष्टिकोण सभ्यतागत गौरव से आत्म-संदेह

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल

और आत्म-आलोचना के युग में परिवर्तित हुआ। पश्चिम का अनुकरण करना स्वीकार्य मानदंड बन गया। स्वतंत्रता के सात दशकों के बाद विकास और सुरक्षा की भावना के पुनरुत्थान की लहर का पुनर्जन्म हुआ है। प्रधान मंत्री ने 2014 से शेर के प्रतीक के साथ मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत की जिसके अंदर गियर, पुली और मशीनरी दर्शाई गई है। मिशन ने भारत में आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने के लिए कई बदलावों की शुरुआत की है। 2011 और 2013 के बीच गिरते रुपये मूल्य के साथ सत्ता में आने के बाद, नई सरकार ने भारतीय को फिर से खड़ा करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप शासन तंत्र में बदलाव किया। 2014 से 2019 तक की सफलता से प्रेरित होकर, 2014 में विरासत में मिली 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाकर, प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से अपनी घोषणा में मात्रात्मक रूप से 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्षेप पथ का आह्वान किया। चीन से शुरू हुई 2020-21 को कोविड महामारी के साथ-साथ चीनी सैन्य एलएसी गतिधरो ने हमारे राष्ट्रीय विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इन बाधाओं के बावजूद भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन का आंकड़ा हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

